

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]

दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 2012/वैशाख 10, 1934

[रा.रा.रा.क्ष.दि. सं. 25

No. 79]

DELHI, MONDAY, APRIL 30, 2012/VAISAKHA 10, 1934

[N.C.T.D. No. 25

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

F. सं. 6/6/2012-न्या./एफसी/297-301.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एवं इस आशय हेतु सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा सुनी बिमला कुमारी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी को परिवार न्यायालय, दिल्ली में उनके दबारा ग्रहण करने की तिथि से न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं।

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND
LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th April, 2012

F. No. 6/6/2012-Judl./FC/297 301.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 3 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, notifies the establishment of one Family Court at

Patiala House Courts Complex having jurisdiction over New Delhi District with effect from 1st May, 2012.

F. सं. 6/6/2012-न्या./एफसी/302—306.—परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का एवं इस आशय हेतु सक्षम बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय की सहमति से एतद्वारा सुनी बिमला कुमारी, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा अधिकारी को परिवार न्यायालय, दिल्ली में उनके दबारा ग्रहण करने की तिथि से न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

F. No. 6/6/2012-Judl./FC/302—306.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Family Courts Act, 1984, and all other powers enabling him in this regard, the Lt. Governor of the NCT of Delhi, with the concurrence of the High Court of Delhi, hereby appoints Ms. Bimla Kumari, an officer of the Delhi Higher Judicial Service, to the post of Judge of Family Court, Delhi, from the date she assumes charge of her office.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अप्रैल, 2012

फा. सं. 07(400)/नीति/वैट/2011/47-60.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, निर्धारित करता हूँ कि समस्त पंजीकृत व्यापारी एवं अनुबंधी (टैन धारक), दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधि नियम, 2004 के अंतर्गत अपने देयकर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य राशि का भुगतान, अधिसूचना सं. फा. सं. 7(400)/नीति/वैट/2011/1006-1018 दिनांक 28-12-2011 तथा फा. सं. (239)/नीति-1/05/वैट/2009/1275-1287 दिनांक 21-2-2012 के द्वारा अधिसूचित 16 बैंकों के अतिरिक्त दिनांक 1-5-2012 से महाराष्ट्र बैंक के ई-पोर्टल द्वारा भी अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक माध्यम से करेंगे।

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप नियम 3 एवं नियम 59 के उप-नियम 2 के उद्देश्य से इन्टरनेट संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर द्वारा किए गए भुगतान के समय छपे यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नंबर (19 अंकीय सी.आई.एन.) वाले चालान के सी पार्ट को रिटर्न के साथ संलग्न होने वाले भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

व्यापारी एवं अनुबंधी (टैन धारक) अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंक से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट ढी की कापी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं।

उपरोक्त बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

‘संलग्नक-1’

ऑन लाइन भुगतान योजना की मुख्य विशेषताएं

(1) व्यापारी/अनुबंधी (टैन धारक) इंटरनेट के द्वारा कहीं से भी और किसी भी समय दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 एवं/अथवा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अपने कर/ब्याज/जुरीने अथवा अन्य किसी देय का भुगतान कर सकते हैं।

(2) यह भुगतान व्यापारी/अनुबंधी (टैन धारक) अथवा उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा संबंधित बैंक की वेबसाइट पर अपने बचत एवं चालू खाते के माध्यम से किया जा सकता है।

(3) यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड एवं अन्य सूचना संबंधित बैंक द्वारा दी जाएगी।

(4) देय-राशि के सफल भुगतान के बाद चालान के सी पार्ट की कापी को छापा जा सकता है।

(5) उपरोक्त चालान का छाप लेने से पहले 19 अंक वाले चालान आइडेंटीफिकेशन नं. (सीआईएन) की जांच कर लें।

(6) व्यापार एवं कर विभाग में अपनी रिटर्न दर्खिल करते समय संबंधित टैक्स पीरियड की रिटर्न के साथ में चालान के सी पार्ट को हस्ताक्षर व मोहर लगाने के बाद संलग्न कर दें।

(7) भुगतान के बाद अपने खाते से डैबिट किए गए भुगतान की जांच कर लें।

(8) चालान का पार्ट ढी संबंधित बैंक द्वारा समुचित हस्ताक्षर व प्रमाणीकरण के बाद भुगतान के बदले में रिकार्ड के लिए भेजा जाएगा।

(9) रात्रि आठ बजे से प्रातः 8 बजे तक किए गए भुगतान को अगले कार्य दिवस के भुगतान में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक किए गए भुगतान को उसी दिन के भुगतान में गिना जाएगा।

(10) रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी समय किए गए भुगतान को अगले कार्य दिवस के भुगतान में गिना जाएगा।

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 30th April, 2012

F. No. 7(400)/Policy/VAT/2011/47—60.—In exercise of the powers conferred under sub-rule 5 of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby prescribe for all registered dealers and contractees (TAN holders) to make payment of their tax, interest, penalty or any other amount due under Delhi Value Added Tax Act, 2004, compulsorily through electronic mode of payment from the e-payment portal of the Maharashtra Bank also, with effect from 1-5-2012, in addition to the banks already notified vide notification No.F. 7(400)/Policy/VAT/2011/1006-1018, dated 28-12-2011 and No.F. 7(239)/P-I/05 VAT/2009/1275-1287 dated 21-2-2012.

Part ‘C’ of the challan having unique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Concerned Bank’s web site) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule 3 of rule 28 and sub-rule 2 of rule 59 of Delhi Value Added Tax Rules, 2005.

The dealers and contractees (TAN holders) will obtain signed and stamped copy of Part ‘D’ of the challan from the concerned bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

The Bank shall adhere to the security and other provisions of Information Technology Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner, Value Added Tax

ANNEXURE-I**SALIENT FEATURES OF THE ON-LINE PAYMENT SCHEME**

1. Dealer/Contractee (TAN holder) can make payment of tax, interest, penalty or any other amount due under Delhi Value Added Tax Act, 2004 and/or Central Sales Tax Act, 1956 through Internet from anywhere and at any time.
2. The payment has to be made from saving/current account of the dealer/Contractee (TAN holder) or any other person on his behalf through web site of the concerned bank.
3. User ID and Password and other information will be provided by the concerned bank.
4. Part 'C' of the Challan may be printed after successful payment of the dues.
5. Check 19 digit Challan Identification Number (CIN) on the challan before printing the same.
6. Enclose Part 'C' of the challan after signing and stamping it with the return of the tax period to which the payment pertains at the time of filing the return with the Department of Trade and Taxes.
7. Check the payment so debited from the account statement after transaction.
8. Part 'D' of the challan will be sent by the concerned bank in lieu of the payment made for record after duly signing and stamping.
9. Payments made after 8.00 p.m. till 8.00 a.m. next day will be accounted in the next working day's payment and payment made between 8.00 a.m. to 8.00 p.m. on any working day will be accounted for the same day.
10. Payments made at any time on Sundays & holidays will be accounted in the next working day's payment.